



सही चुनौं

सभी चुनौं



# राष्ट्रीय नवीन मेल

रांची एवं डालटनगंज (मेदिनीनगर) से एक साथ प्रकाशित

तैयारी कृष्ण पक्ष 04, सवत 2081 | रांची, रविवार, 28 अप्रैल 2024, वर्ष-25, अंक-86, पृष्ठ-12 | मूल्य ₹3.00 | रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155 | www.rastrianaveenmail.com

सत्यगेव जयते



पेज-12

संसेक्स 73,730.16 ▾ -609.28

डॉलर 83,404 ▲ +0.13

रांची सराफा

सोना (10 ग्राम) 67,250

चांदी (1 किलो) 88,000

आज के मैच

समय : 28 अप्रैल, 3:30 बजे से

स्थान : अहमदबाद

विप्रीहाल क्रिकेट क्लिंपिंग

समय : 28 अप्रैल, 7:30 बजे से

स्थान : चेन्नई

क्राउट्स-एप सीधे जुड़ें

1994 से अनवरत हम आपके

लिए समाचारों की प्रमुखता की

नीति पर कार्य करते रहे हैं। इसे

और सुगम बनाने के लिए एक

विशेष क्राउट्स-एप नंबर है, जिसमें

आप सभी अपनी परखी हुई

सच्ची खबर फोटो सहित क्षेत्र

में इस नंबर 53444 पर

भेज सकते हैं। आपनिजनक

समझी भेजने पर आइटीएफ के

अंतर्गत कार्यालय हो सकती है।

यदि आपको अखबार की प्रति

नहीं मिल पा रही है या विज्ञापन

देना चाहते हैं तो इस नंबर पर

8292373444 संपर्क करें।

एक नजर

ज्ञानमो ने खेलगांव को

हेलीकॉप्टर पार्किंग बनाया

भाजपा पहुंची आयोग

रांची। भाजपा का एक

प्रतिनिधिमंडल शनिवार को

चुनाव आयोग पहुंचा और

ज्ञानमो द्वारा खेलगांव में

हेलीकॉप्टर पार्किंग बनाने पर

विरोध दर्ज करते हुए मुख्य

चुनाव पदाधिकारी को ज्ञानम

सांगा। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा

विधि प्रक्रिया के प्रदेश संघोंजक

सुधीर श्रीवाच्तव्य न्यायिक

मामलों के उप प्रमुख राज्य झा

और अधिकारी शिव कुमार शर्मा

शामिल थे। सुधीर श्रीवाच्तव्य ने

बताया की ज्ञानमो ने खेलगांव

को हेलीकॉप्टर पार्किंग बना

लिया है। यह किसके आदेश

पर किया गया, अभी तक कितना

बार यहां पर रही है या विज्ञापन

देना चाहते हैं तो इस नंबर पर

8292373444 संपर्क करें।

आजकल

पुलिस हत्या और

आत्महत्या के एंगल से

कर रही है जांच

नवीन मेल संवाददाता। गढ़वा

गढ़वा जिले के विशुनुपुरा के प्रखण्ड

विकास परिवारी हार्म कमनान

केरेकटा का शब शनिवार की

दोपहर उनके आवास पर फंडे से

झलता मिला। जैसे ही यह खबर

फैली प्रसारित हुई

अधिकारियों के

साथ ही आमतोंगों में सनसनी फैल

गई। जानकारी के अनुसार जब

ब्लॉक स्टाफ दोपहर तीव्र बजे

किसी कागजात पर उनसे हस्ताक्षर

करने गए तो दरवाजा बंद था।

व्यापा...

असाम संसद लाला

आग

व्यापा...

असाम संसद लाला









## एक नजर

संकेत हार्ट स्कूल में  
मतदाता जागरूकता विजय  
प्रतियोगिता आयोजित

झुमरीतिलैया। कोडरमा लाकसभा का चूनाव 20 मई को होता है। इसी कड़ी में संकेत हार्ट स्कूल में शनिवार को इंटर हाउस मतदाता जागरूकता विजय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कलास नवीन और 10 वीं के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता शिक्षक शंकर कुमार की देखरेख में हुई। प्रतियोगिता में बबलू, राजवीर, अधिकारी, शैल्य सिंह, दीपांकित राज, राजा बाबू गौतम, श्वेतम् कुमार, पीषा कुमार मोदी, स्वास्तिक कुमार, तम्य सेठ, मोहित राज, सुष्टि मिश्र, दिव्यका बबलू, शिवम् कुमार, सचिन कुमार, शैर्वि तिवारी, ऋषिका, निशा राज, शौरी राज, निखिल राज ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रत्येक हाउस के लिए कुल 50 अंक निर्धारित थे।

**भाक्पा माले को खटक रहा**

आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिल रहा आरक्षण: रसेना सिंह कोडरमा। भाजपा के वरीय नेता रमेश सिंह ने कहा है कि भाक्पा माले को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को मिल रहा 10 प्रतिशत आरक्षण खटक रहा है। भाक्पा माले अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खटक रहा बाया कर रही है कि यदि इंडी गठबंधन सत्ता में आया, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को मिल रहा 10 प्रतिशत आरक्षण समान लिया जाएगा। भाक्पा माले के इस रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और विशेषज्ञ गरीब सर्वों में आक्रोश है और माले को इसका ख्वामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंह ने कहा कि प्रश्नान्वयनी ने देंद्र मोदी और भाजपा की पलट पर आजादी के बाहर पहल बार अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण या संबंधित से वर्चित गरीब सर्वों सहित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ।

**झुमरीतिलैया नगर परिषद महागठबंधन दलों की बैठक में कई निर्णय**

झुमरीतिलैया। नगर परिषद बैठक में महागठबंधन की मजबूती और हार्ट बूथ तक जनता से सीधे संवाद को लेकर जमीन पर उतारने में जुटी है। इसी को लेकर महागठबंधन की विजयनुभूति रोड स्ट्रिट राष्ट्र नेता सुभाष प्रसाद बादव के आवास पर बैठक शुक्रवार को हुई। महागठबंधन के जिला संघेजक रामधार साहब ने कहा कि यह बार लोकसभा साहब ने अपने जिला विजयनाम स्वीकृति दिलाई है। उत्तरने कहा कि भाजपा 10 साल से सत्ता में है। लेकिन इस दौरान कोडरमा को जनता का कांड भालाई का काम नहीं हुआ। शिक्षा विजयांग में मंत्री रहते हुए की उपलब्धि जनता को पिनाने के लिए भाजपा के पास जबाब नहीं है। उत्तरने कहा कि संविधान, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उत्तरने कहा कि महागठबंधन एकता के बाहर पर शर्मी क्षेत्र में भी भाजपा को हर वर्ष पहुंचा रहा है। बैठक को कर्मसूलीय नेता संसदीय अपाप के द्वारा बादव, बसपा नेता प्रकाश अंडेकर, विलात पर्वतविर इंद्रदेव राम ने कहा कि दुनिया में वह शहर विश्व विजयांग है।

**सरहुल मानव जाति को प्रकृति की रक्षा करने का संदेश देता है: विधायक भूषण बाड़ा**



नवीन मेल संवाददाता। सिमडेंगा

प्रकृतिक पूजा कर एक दूसरे के साथ खुशियां बाटों आए हैं। सरहुल का मनुष्य और प्रतिशत स्थित क्षेत्र बाहर में एवं पुलिस अधीकारी सारे भ्रम भारत ने लोकसभा अम चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर बाने प्रखण्ड का प्रमाण किया। इस दौरान उत्तरने राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय हाटिंगहोड़े में भवन मम्मती कार्य को चार से पांच दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पानी, शौचालय, पोलिंग पार्टी के ठहरने के लिए कार्य, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य सुधारों को जायजा लेने हुए प्रबुद्ध विकास पदाधिकारी बाने बहुत गतिशील पूर्ण है।

जिसमें हामरे पूर्वजों के द्वारा भरती व

निर्णय दिया गया है।

**मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं का किया गया स्वागत**



नवीन मेल संवाददाता। सिमडेंगा

सुविधाओं को दिखाते हुए उल्लेख किया गया। उत्तरने कहा है कि विद्यालय एक परिवार की तरह है और उत्तरने अधिकारीवालों से अपील की जिसे हम अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से देंगे अपनी भी बच्चों को समय दें ताकि इनका बेहतर व्यवस्था बनाया जा सके। एसोसिएट एसोसिएट अंपसर सल्यांजत कुमार के द्वारा पौरी की

विद्यालय के सभी संसाधन एवं

सम्पादन के साथ संसाधन एवं

संविधान एवं विद्यालय के सभी संसाधन एवं

सम्पादन के साथ संसाधन एवं

सम्पादन के



पुस्तक समीक्षा

गोदियनकंसैसस

द रिडिस्कवरी ऑफ भारत

The image shows the front cover of the book 'Modian Consensus: The Rediscovery of Bihar'. The title is at the top in large letters, followed by the subtitle 'THE REDISCOVERY OF BIHAR' and the author's name 'Swadesh Singh'. To the left of the text is a portrait of a woman in a black and white sari. To the right is a portrait of Prime Minister Narendra Modi with his hands joined in a Namaste gesture. In the background, there is another person wearing a red turban and a gold chain.

है। यह हाल के वर्षों की राजनीति की उल्लेखनीय विशेषताओं का भी वर्णन करता है। लेखक विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए और 19वीं सदी के अंत तक जाकर मोदी की राजनीति की वैचारिक जड़ों का पता लगाता है। हालांकि यह मोदी फैक्टर पर विचार करता है, लेकिन यह इसके बाहर और आगे भी देखता है। यह पुस्तक पूरी तरह से नया विष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि कैसे पीएम मोदी ने भारत में राजनीति के विमर्श को बदल दिया। न केवल भाजपा अपनी राजनीति कैसे करती है बल्कि उन्होंने अन्य सभी राजनीतिक दलों को एक अलग तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया। मोदियनसर्वसम्पत्ति, जिसे तीन खंडों और दस अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, सर्वसम्पत्ति को पांच चरणों में वर्गीकृत करती है: सम्भातवादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, धर्मनिरपेक्ष और मोदियन, जो सबसे हालिया है। तीन मानदंड, मुखर राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक जड़ता और सभी के लिए कल्याण, नंदें मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में इस नए अध्याय को शुरूआत की विशेषता है। पश्चिम द्वारा थोपे गए भारत के विकृत छवि का खंडन करने और 'भारत राष्ट्र' की एक अलग तस्वीर पेश करने के लिए देश के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण करना पुस्तक के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय

तक स्वदेश सिंह ने सर्वसम्मति का अथं, कई कोणों से विस्तार से बताया और यह यात्रा कई कालखंडों से होकर गुज़रा है। श्री सिंह ने ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्वक स्वदेशी आंदोलन, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के आगमन, नेहरूवादी सहमति, लुप्त होती नेहरूवादी सहमति और धर्मनिरपेक्ष सर्वसम्मति के बारे में लिखा। उनका दावा है कि नेहरू की संकीर्णता, खराब राजनीतिक प्रयोग और भारतीय समाज के बारे में गलत धारणा ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया - चाहे वह चीन के संबंध में हो, कश्मीर विवाद हो, या पंचवर्षीय योजनाओं में अंतराल हो। आगे लेखक, मोदी शासन और मोदी सरकार 2.0 की व्याख्या करते हैं। यह हमें पुस्तक के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग में लाता है, जहां चर्चा की गई है कि 2014 में मोदी सरकार कैसे सत्ता में आई और तब से राजनीतिक परिवर्ष्य कैसे बदल गया है। अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के साथ मोदी की आम सहमति के तीन मुख्य सिद्धांतों - सांस्कृतिक जड़ता, आक्रमक राष्ट्रवाद और सभी का कल्याण - पर केंद्रित होकर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लोगों को नई आशा और आकंक्षाएं दीं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने आधुनिक लक्ष्यों को भारत के प्राचीन गौरव के साथ जोड़कर सफलतापूर्वक दो कार्यकालों तक शासन किया। योग को विश्व मंच पर ले जाने से लेकर भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वैश्विक, स्थानीय और मुख्य पहचान दिलाने तक, पीएम मोदी ने यह सब सुनिश्चित किया। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि कैसे मुख्य राष्ट्रवाद का विचार न केवल नरेंद्र मोदी द्वारा पेश की गई राजनीति को अर्थ देता है, बल्कि 2014 से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय विदेश नीति में जो कुछ भी गलत था, उसे भी सामने लाता है। पिछले दस वर्षों में, पीएम मोदी ने सदैव 'राष्ट्र-प्रथम' की संकल्पना से कार्य किया है। संपूर्ण रूपसे यह पुस्तक पठनीय है।



डा. मयक  
चतुर्वेदी

इस तरह का कृत्य करे या इससे जुड़े नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नक्सलियों से मिलते हों अथवा उनके समर्थन आगे आएं, तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस नक्सलवाद का विरोध करती है ? छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कांकेर में मारे गए माओवादी (नक्सली) नेता सिरीपेल सुधाकर उर्फ शंकर राव के घर कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में मंत्री अनुसुद्धा दानसाह उर्फ सीताकाका अभी कुछ दिन पहले ही पहुंचा और अपना उनका इससे जुड़ा वीडियो भी वायरल है। जबकि राज्य सर्वविदित है कि नक्सली आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति सुधाकर कई हिंसक घटनाओं में शामिल था और सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी। अब आप ही विचारें; कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और एक राज्य तेलंगाना में मंत्री भी हो, वह किसी नक्सली के घर जाकर उसके परिवार के सामने संवेदना व्यक्त करे तो उसके इस कृत्य को क्या माना जाए? क्या यह देशभक्ति है या देशद्रोह? ऐसे में विचार करने का लोग आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता का यह आचरण केवल चरमपर्याप्ति, वामपर्याप्ति कार्यों को महिमापूर्णित करने और उसे वैध बनाने के काम आता है। साथ ही यह कानून व्यवस्था बनाए रखने सुरक्षा बलों के प्रयासों को कमज़ोर करते हैं। प्रश्न यह कि क्या यह पहली घटना है, जब किसी नक्सली के प्रयासों के नेता द्वारा हमदर्दी जारी गई। वस्तुतः छत्तीसगढ़ के जंगल में सुरक्षाबलों ने चार घंटे तक चली मुठभेड़ जब 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है, तब इस

पम्प, रातू, रांची-835222, झारखण्ड द्वारा मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155, प्रधान संपादक : मेदिनीनगर (डालटनगंज) पलामू-822102, फोन नंबर : 06562-796018, रांची कार्यालय : 502बी, article.rnmail@gmail.com (\*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार।)

# बैलेट पेपर व वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

वैशिक स्तरपर दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऐसा भी एक जमाना था जब हम बैलेट पेपर के द्वारा अपना वोट देते थे। यानें अपने मनपसंद उम्मीदवार और उसके चुनाव चिन्ह पर ठप्पा लगाते थे। इस व्यवस्था के दुष्प्रभाव में हमने दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर बृथ कैपचरिंग सहित बैलेट पेपरों पर धड़ाधड़ ठप्पे लगाते पेटी में डालते हुए भी चैनलों में देखे थे तथा लाइनों में खड़े मतदाताओं को भगा दिया जाता था यह भी मैंने चैनलों पर स्वयं देखा था। फिर समय का चक्कर ऐसा चला कि प्रौद्योगिकी का तेजी के साथ विकास हुआ तो मतदान में बैलेट पेपर से हटकर ईवीएम मशीनों का उपयोग कर दिया जाने लगा। फिर हमने ईवीएम की गड़बड़ियों के बारे में भी अनेक आरोप प्रत्यारोप मीडिया में देखे व सुने फिर वोवीपीएटी आया, जिसमें हम देख सकते हैं कि वोट हमारे पसंदीदा उम्मीदवार को गया या नहीं, जो मैंने स्वयं ने भी 19 अप्रैल 2024 को मतदान के दौरान यह देखा, फिर इसकी पर्चियों का 100 प्रतिशत क्रॉस वेरिफिकेशन का मुद्दा आया यह सभी मुद्दे विवादों में घिरत हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पक्षों को नोटिस जारी कर मुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा था, जो दिनांक 26 अप्रैल 2024 को माननीय दो जजों की बेंच ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वालीपीएटी स्लिपों की 100 प्रतिशत क्रॉस चेकिंग की याचिका

का खारिज कर दिया जिसका चैप्टर अब दि एंड हो गया है। चूंके बैलेट पेपर व एवं वीवीपैट एटी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, इसीलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस अर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर व एवं वीवीपैट एटी का शतप्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है, परंतु फैसले का सम्मान सभी पक्ष करेंगे। साथियों बात अगर हम दिनांक 26 अप्रैल 2024 को आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करें तो, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वैरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से इंडिया एम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्यायों से शत-प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है। एससी ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा। याने मतदान तो इंडिया एम से ही होगा, इसके साथ ही वीवीपैट से 100 फीसदी पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि, इंडिया एम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। एससी ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। माननीय जस्टिसने

अगर हम माननीय कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा रखे गए पक्ष की करें तो, चुनाव आयोग के अधिकारी ने कोर्ट नम 26 अप्रैल 2024 को आए माननीय की करें तो, लोस चुनाव के दूसरे चरण की को सुनीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट र दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। इंडीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट नेशनल मिलान की मांग को झटका लगा है।



को बताया कि एक वोटिंग यूनिट में एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपीएटी यूनिट होती है। सभी यूनिट में अपना अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है। इन कंट्रोलर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सभी माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम फाईड किया जा सकता है। चुनाव चिह्न अपलोड करने के लिए हमारा पास दो पैन्यूफैक्चर हैं, एक इंसीआई है और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी इंडीएम 45 दिन तक स्ट्रॉन्नर रूम में सुरक्षित रखी जाती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार, इलेक्शन कमीशन से

इस बात को पुष्टि की जाती है कि क्या चुनाव को लेकर कोई याचिका तो दायर नहीं हुई है। अगर अर्जी दायर नहीं होती है तो स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता। कोई याचिका दायर होने की सूरत में स्ट्रॉन्ग रूम को सीलबन्ड रखा जाता है। बुधवार को एससी ने कहा था कि अदालत चुनाव की नियंत्रण अर्थारिटी नहीं है। अदालत ने ईवीएम मुद्रे पर दो बार दखल दिया है। बेंच ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वीवीपीएटी पर दो आदेश जारी किए हैं, जो एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है और मतदाताओं को यह देखने में सक्षम बनाती है कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा, एक आदेश तब पारित किया गया था जब अदालत ने चुनावों के दौरान वीवीपैट के उपयोग का आदेश दिया था और दूसरा आदेश तब पारित किया गया था जब अदालत ने निर्देश दिया था कि वीवीपैट का उपयोग एक से बढ़ाकर पांच बूथों तक किया जाना चाहिए। अब आप सभी चाहते हैं कि हम मतपत्रों पर वापस जाने के लिए निर्देश जारी करें। बेंच ने कहा, यदि जरूरी हुआ तो वो मौजूदा ईवीएम सिस्टम को मजबूत करने के लिए निर्देश पारित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में चुनाव आयोग से कहा था कि किसी संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ वीवीपैट की संख्या एक से बढ़ाकर पांच कर दी जाए। साथियों बात अगर हम इस केस और फैसले के असर को सभी पक्षकारों के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो, केस और फैसले के असर को इन सभी पक्षों के नजरिए से समझते हैं। (1) आम आदमी यानी मतदातासुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप आदमी की वोट देने की प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। वोटर पोलिंग बूथ जाएगा। अमंतु पर स्थानी लगेगी। चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएगा। वोटर बैलट यूनिट में कैडिडेट के नाम के सामने का बटन दबाएगा और फिर कुछ सेकेंड तक वीवीपैट की लाइट में अपनी पर्ची देख सकेगा। (2) राजनीतिक पार्टियां और कैडिडेट्स, फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां और कैडिडेट्स के लिए एक रास्ता खुला है। वे ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। इसे नीचे दिए पाइंट्स से समझिए। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैडिडेट को शक है तो वह रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकता है शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम में से 5 प्रतिशत मशीनों की जांच हो सकती है। इन 5 प्रतिशत ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा इस जांच का खर्च कैडिडेट को ही उठाना होगा। चुनाव आयोग ने बताया-जांच की समय सीमा और खर्च को लेकर जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी। (ये लेखक के निजी विचार हैं।)

6

व से है 'सतीया'

**ਲਿੰਗੁਤ ਨਾ ਹੈ ਜਾਗਰਾਧ ਜਾਪਨ  
ਮੂਲਿਆਂ ਪਰ ਸੰਕਟ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ'**

**हृदयनारायण दीक्षित**

अन्य कालखण्ड में इस तरह का मानवीय संकट नहीं था। मानचार माध्यम भी जब कब विश्ववुद्ध की आशंका की बातें करते हैं। विचार ही मनुष्य जाति के वाद्य स्वरूप और आंतरिक उदात्त भाव के प्रसारक रहे हैं। विचार भी अपना प्रभाव खो रहे हैं। मानवीय सभ्यता आधुनिक काल का मनुष्य विरोधी प्रेरक तत्व बन गई है। वातावरण में निश्चिन्तता नहीं है। सदैह और अनिश्चितता का वातावरण है। मनुष्य जाति भवित्व के भय से डरी हुई है। धन का प्रभाव और धन का अभाव दोनों ही मारक हैं। मानवता का बड़ा भाग पर्याप्त भोजन से वंचित है। इस वर्ग में सामान्य चिकित्सा और शिक्षा, आश्रय-घर का अभाव है। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में अभावग्रस्त लोगों के सामने संकट है। विज्ञान के जानकार प्रकृति के तमाम रहस्य बता रहे हैं। निःसंदेह वैज्ञानिक शांथों ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शांथों ने पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व के समाप्त होने का खतरा पैदा कर दिया है। युद्ध के तमाम आश्वर्यजनक हथियार पृथ्वी और मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। परमाणु हथियार सहित अनेक आश्वर्यजनक अस्त्रों की खोजों से पृथ्वी के ही अस्तित्व पर खतरा है। पृथ्वी ग्रह संकट में है और उससे पोषण पाने वाली मानव जाति भी संकट में है। वैज्ञानिकों ने तपाम् ग्रहों की गतिविधि का पता लगा लिया है। आशंका है कि किसी समय पृथ्वी चन्द्रमा के निकट पहुंच सकती है। सूर्य का ईंधन लाखों वर्ष से खर्च हो रहा है। सूर्य के ठंडा हो जाने से ही मनुष्य

2 - . . . 1

**लाल आतंक से प्रेम कर अपने पैर पर कुळ्हाड़ी मानती कांग्रेस**

लैए सुरक्षावता का पाठ यथोपान का जगह काप्रेस प्रवत्तन सुप्रिया श्रीनेत नक्सलियों को महिमांदित करने का काम करती दिखती हैं, वह मारे गए नक्सलियों को 'शहीद बताती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाल की इस पर प्रतिक्रिया भी आई, उन्होंने कहा भी कि 'यह वही नक्सली हैं जिन पर 25 लाख का इनाम है लेकिन काप्रेस कहती है जो शहीद हुए हैं उनकी जांच होने चाहिए।' एक बयान छत्तीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भपेश बघेल का भी खूब चचार्में रहा, उन्होंने तो हद हौं कर दी कह रहे हैं कि 'जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है। अभी चार महीने में फिर से फर्जी एनकाउंटर में वृद्धि हुई है। नक्सली बताकर बनवासियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा उन्ने डराया-धमकाया जाने लगा है। बस्तर और कांकेर जैसे क्षेत्रों में ये चल रहा है। इस प्रकार की घटनाओं की वृद्धि हो रही है।' विचार करें, क्या इस प्रकार के प्रमुख काप्रेस नेताओं के बयान से नक्सलियों का मनोबल नहीं बढ़ता होगा अगले साल छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नरसंहार को 11 साल पूरे हो जाएंगे। इस सबसे बड़े नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ काप्रेस की प्रथम पंक्ति के कई नेता मारे गए थे। कई जवासी भी बलिदान हुए थे। इस मामले में अब तक की जांच किर्सन नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में हमले में मारे गए काप्रेस नेता और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने काप्रेस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने हमले में जीवित बचे काप्रेसी नेताओं का नार्को टेस्ट कराया की मांग की है। साथ ही कहा कि नक्सलियों का ऐसा क्या प्रेम, जो कवासी लखमा बचकर आ जाते हैं। कोटा से कवासी लखमा विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से यात्रा निकाल रही थी। ऐसे में उनकी जवाबदारी सुरक्षित यात्रा की थी लेकिन आश्वश्व है कि नक्सली हमला करते हैं और लखमा जी बचके आ जाते हैं, बाकी लोग बलिदान होते हैं। क्यों ! नक्सलियों का ऐसा क्या प्रेम है लखमा जी से मेरे पिता नहीं रहे। मेरा नुकसान हुआ। मैं अभी भी ढक्के की चोट पर कहता हूं कि इस हमले में बचकर आए सर्थी नेताओं का नार्को होना चाहिए। इस नक्सली हमले के

हृदयवारादकता इतना आधिक था कि नक्सलीलयों ने बर्र-टाइगर महेंद्र कर्मा को करारी 100 गोलियां मारीं और चाहे से उनका शरीर पूरी तरह छलनी कर दिया था। नक्सलियों ने उनके शव पर चढ़कर डांस भी किया था। इसी प्रकार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का नक्सली समर्थक बयान सामने आ चुका है। जिस पर पिछले वर्ष भाजपा ने वरिष्ठ नेता बुजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ही नक्सल समस्या की जननी अँड़ी संरक्षक बताया था। साथ ही कहा कि देश और प्रदेश वे विकास को नक्सलियों ने अवरुद्ध किया। शहरों में रहने वाले नक्सलियों के समर्थकों ने विकास को रोका। कांग्रेसियों में नक्सलियों के प्रति सांपत्कार्नर हैं जोकि देश के लिए बहुत धातक है। दरअसल, सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि सभी नक्सली लोग गलत नहीं होते। बहुत लोगों व गलत तरीके से फायदा उठाया जाता जाता है। बहुत लोग उनके नाम से ढकानें चला रहे होते हैं। वह भी इंसान है हम भी इंसान हैं तो डर कैसा। जो लोग यह पैदा कर रहे हैं वह नहीं चाहते कि शांति बहाल हो। यानी कि एक तरफ से सांसद रंजीत रंजन ने नक्सलियों को भोला-भाला इंसान करार दिया था, जोकि कई भोलेभाले आमजन, नेताओं और पुलिस फोर्स, सैनिकों के हत्यारे हैं। यह भी एक तथ्य है कि वर्ष 2018 में प्रतिबंधित नक्सलियों से साठगढ़ देश आरोप में गिरफ्तार और नजरबद तत्कालीन 10 लोगों देश पास मिले दस्तावेजों से देश में अस्थिरता फैलाने की बड़ी साजिश का संकेत मिला था। चौंकाने वाली बात यह है कि नक्सलियों की मदद कर रहे ‘शहरी नक्सली’ इस मामले में कांग्रेस की सहायता मिलने का भी दावा कर रहे थे। भीमा कोरेंगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन देश लैपटॉप में एक बड़े नक्सली नेता की ईमेल मिली। ईमेल में ‘कामरेड एम’ ने दलित आंदोलन की आड़ में देश अस्थिरता फैलाने में कांग्रेस का साथ मिलने का दावा किया गया था। विल्सन को भेजी ईमेल में लिखा गया कि शहर में रहने वाला शीर्ष नक्सल नेतृत्व कांग्रेस में हमारे कुदास्तों के साथ संपर्क में है। वे दलित आंदोलन को और भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं।

माना कारणाव हस के दो दिन बाद हा लिखा इसके बहाने चले आंदोलन को काफी सफल बताया गया। इसके साथ ही हिंसा में एक व्यक्ति की मौत को मुद्दा बनाने हुए आगे भी आंदोलन चलाने और इसके लिए दुष्प्रचार सामर्थ्य तैयार करने का निर्देश दिया गया था। 'कामरेड एम' ने अनुसार नक्सल नेतृत्व ने भीमा कोरेंगांव हिंसा के लिए कामरेड सुधीर को दो बार फंड भेजा था। इसके साथ आगे के आंदोलन के लिए जरूरी फंड की जिम्मेदारी कामरेड शोमा और कामरेड सुरेंद्र को सौंपी गई। 'कामरेड एम' ने रोना विल्सन को बताया है कि किस तरह नक्सली नेतृत्व भीमा कोरेंगांव की तर्ज पर अन्य भाजपा शासित राज्यों में उग्र दलित आंदोलन खड़ा करने की तैयारी जुटा है। इस काम में जुटे विश्वरूपा, सुदीप, मुशील और देवजानी का मोबाइल नंबर भी दिया गया। इसमें मैं यह साक्ष्य महत्वपूर्ण है कि रोना विल्सन ने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तर्ज पर प्रधानमंत्री नंदेंद्र मादी की हत्या की सजिश का सुझाव अपनी ईमेल में नक्सली नेतृत्व विद्या था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रोना विल्सन वह जून में ही गिरफतार कर लिया गया था। वस्तुतः आज हम यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि देश के 11 राज्य नक्सल से प्रभावित हैं। कुल 90 जिलों में नक्सली हिंसा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य हैं- छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही घटनाएं इसके तस्दीक करती हैं, जहां नक्सली हर साल कई बार सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हैं। हजारों जानें ऐसे हमले में जा चुकी हैं और साल दर साल जा रही हैं। ये नक्सली दावा करते हैं कि वे बनवासियों, छोटे किसानों और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा जनकल्याण की योजनाओं तक वह आरंभ नहीं होने देते हैं। अपने डर के साए में लोगों वर रखते हैं और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जान-बूझकारी दूर रखते हैं ताकि उनके मन में शासन के प्रति विद्रोह व भावना भरना आसान हो जाए।

वेट लिमिटेड (पूर्व में शिवासाई पब्लिक







